

भारत सरकार  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2128  
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

अदोहित ऑफशोर पवन ऊर्जा क्षमता

2128. श्री चरनजीत सिंह चन्नी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि देश की ऑफशोर पवन ऊर्जा क्षमता अभी भी काफी हद तक अदोहित है, जबकि डेनमार्क, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लवणता प्रवणताओं का उपयोग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत स्टेशन स्थापित करने की व्यापक गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए ऑफशोर पवन ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): वर्तमान में देश में कोई अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित नहीं है। तथापि, सरकार ने देश में अपतटीय पवन ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। इनमें, अन्य के साथ-साथ, शामिल हैं;

- देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की रूपरेखा प्रदान करने हेतु अक्टूबर, 2015 में 'अपतटीय पवन ऊर्जा नीति' की अधिसूचना।
- इच्छुक डेवलपर्स द्वारा अपतटीय पवन अध्ययन/सर्वेक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा सितंबर, 2018 में 'अपतटीय पवन विद्युत मूल्यांकन, अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए दिशानिर्देश' जारी किए गए।
- विकास के प्रारंभिक चरण के लिए, मेसो-स्केल अध्ययन के माध्यम से गुजरात और तमिलनाडु के तट से दूर संभावित अपतटीय पवन क्षेत्रों को चिह्नित किया गया।
- नवंबर, 2017 में गुजरात के अपतट पर नीवे द्वारा लिडार की स्थापना और 02 वर्षों के पवन डेटा का संग्रहण। नीवे ने गुजरात के अपतट पर 1 गीगावाट क्षमता के समतुल्य स्थल का भूभौतिकीय, भू-तकनीकी अध्ययन, रैपिड ईआईए अध्ययन, समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन (लहर, ज्वार और धारा) भी किया है।
- तमिलनाडु अपतट पर तीन बोर होल स्थलों पर भू-तकनीकी अध्ययन किया गया। इसके अलावा, पवन संसाधन मापन हेतु तमिलनाडु अपतट पर 4 लिडार स्थापित किए गए।

- जुलाई, 2022 में 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र' जारी किया, जिसमें विभिन्न विकास मॉडलों का उल्लेख किया गया।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियमावली, 2023 को अधिसूचित किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) ने प्रारंभिक 10 गीगावाट अपतटीय ट्रांसमिशन क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक तट पर 5-5 गीगावाट) की आयोजना (प्लानिंग) पूरी कर ली है।
- सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के माध्यम से कैप्टिव मोड/द्विपक्षीय समझौतों/ओपन एक्सेस मोड के तहत '4 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समुद्र तट को पट्टे पर देना' के लिए प्रथम निविदा जारी की है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.06.2024 को 7453 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना' को स्वीकृति दी है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के अपतट पर 500-500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए 6853 करोड़ रु. का परिव्यय तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लाजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रु. का अनुदान शामिल है। दिनांक 11 सितंबर, 2024 को "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना" के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए गए।
- सेकी ने वीजीएफ योजना के तहत दिनांक 13 सितंबर, 2024 को गुजरात के अपतट पर 500 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा जारी की है।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार द्विपक्षीय/सहयोगात्मक दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए मान्य गतिविधियों की सूची में अपतटीय पवन को शामिल किया गया है।
- दिनांक 31.12.2032 को या उससे पूर्व चालू की गई अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन (आईएसटीएस) शुल्क में छूट में वृद्धि कर दी गई है, इसके बाद ग्रेडेड आईएसटीएस शुल्क लागू होंगे।
- दिसंबर, 2032 तक चालू की गई अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत के लिए अतिरिक्त अधिभार से छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी)" कार्यक्रम को लागू कर रही है ताकि देश में कुशल और किफायती तरीके से महासागर ऊर्जा लवणता ग्रेडिएंट सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और निर्माण का विकास किया जा सके।

\*\*\*\*\*